



देश की स्वतंत्रता में विद्वानों की भूमिका

डॉ. विजय शंकर कौशिक, सहायक आचार्य (इतिहास विभाग)

प्रस्तावित अनुसंधान की भूमिका

स्वतंत्रता के संघर्ष में उग्रदल ने और अधिक अतिवादी होकर देश में आतंक स्थापित करने वाली ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह का वातावरण निर्मित किया क्या संघर्षशील सशस्त्र प्रगति का मार्ग चुना। इस संघर्ष के पीछे निश्चय ही राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक और सामाजिक कारण रहे हैं जिन्होंने मूल प्रेक सत्य के रूप में स्वाधीनता संघर्ष को गति प्रदान किया। ब्रिटिश शासन को स्थान-स्थान भारतीय जनता के विरोध का सामना करना पड़ा था जो कार्य स्थानीय राजे-महाराजे नहीं कर सके थे, उन कार्यों को साधारण जनता ने किया था। प्रतिरोध करने वाली साधारण जनता में पर जमींदार, धर्म-परायण तथा समाज के अन्य वर्ग सम्मिलित थे जिनके हितों को ब्रिटिश शासन से आघात पहुँचाया था। बस्तुतः विदेशी प्रभुत्व के आर्थिक शोषण और प्रशासनिक दुर्बलता के जनमानस में तीव्र प्रतिक्रिया को जन्म दिया। परिणामस्वरूप, विदेशी शासन का भारत के विभिन्न भागों में अक्सर विरोध किया जाता रहा। जिस विरोध को आन्दोलन सम्मिलित था। एच्च शिक्षा प्राप्त करके लोग विश्वविद्यालयों से बाहर आने लगे। किन्तु ऐसे योग्य लोगों की अपेक्षा की तुलना में कोई भी उच्च सरकारी पदे नहीं मिलते थे और ऐसे भारतीयों को हेय दृष्टि से देखा जाता था। पदों के लिए आई.सी.एस. की परीक्षा केवल इंग्लैण्ड में आयोजित होती थी, जबकि दादाभाई नौरोजी का यह तर्क था कि यह परीक्षा भारत में भी साथ-साथ आयोजित की जानी चाहिए ताकि अधिक से अधिक भारतीय इसमें शामिल हो सकें, किन्तु ब्रिटिश भारत सरकार ने इसे अस्वीकार कर दिया। फलस्वरूप देश में धीरे-धीरे राष्ट्रीय शिक्षा की आवश्यकता का अनुभव किया जाने लगा। देश के नेता राष्ट्रीय विचारधारा और ब्रिटिश नियंत्रण से मुक्त शिक्षा संस्थाओं के निर्माण पर कार्य करने लगे। राष्ट्रीय शिक्षा के निमित्त महामना मालवीय, रीन्द्रनाथ टैगोर, हीरेन्द्रनाथ दत्त, विपिन चन्द्र पाल तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने यह निश्चय किया कि राष्ट्रीय शिक्षा के निमित्त नए राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की जाये। इस सम्बन्ध में छात्रों का आन्दोलन भी प्रारम्भ हो गया। जिसे दबाने के लिए सरकारी तन्त्र का उपयोग किया जाने लगा। इसी साल मार्च 1906 ई. में राष्ट्रीय शिक्षा के हितों के लिए 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' की स्थापना की गई तथा इसके लिए अरविन्द और गुरुदास दास बनर्जी का आशीर्वाद प्राप्त किया गया। इस नए राष्ट्रीय विचारधारा के प्रमुख वक्ता विपिन चन्द्र पाल थे। ए.आर. देसाई ने लिखा है कि देश में शिक्षितों की संख्या बढ़ती गई और उनमें वर्तमान प्रशासन के विरुद्ध असन्तोष व्याप्त हो चला था। शिक्षा पर नियन्त्रण स्थापित करने के साथ-साथ ब्रिटिश सरकार ने प्रेस और समाचार पत्रों पर अनेक प्रतिबन्ध लगाया तथा उनकी स्वतन्त्र रीति पर कड़ी नजर रखी अतः आपत्ति-जनक सामग्री के प्रकाशन और वितरण पर सरकार द्वारा पाबन्दियाँ लगाये जाने से शिक्षित जनता में सरकारी नीति के प्रति असन्तोष उत्पन्न हुआ, जिसने युद्धोन्मुखी आन्दोलन को प्रेरित किया। समय-समय पर अधिनियम पारित किये। सरकार ने ऐसे अनेक नियन्त्रण युक्त 1823 ई. के एक अधिनियम के अनुसार सरकार को यह अधिकार था कि वह आपत्ति-जनक सामग्री के कारण किसी भी समाचार पत्र या पुस्तक को जब्त कर सकती थी। इस अधिनियम का राजाराम मोहन राय और टाकुर द्वारिका नाथ ने विरोध किया था।

प्रस्तावित अनुसंधान के स्रोत

स्वामी विवेकानन्द ने अपने आध्यात्मिक विचारों और संदेशों से समस्त हिंदू जनता के मस्तिष्क को आंदोलित कर दिया तथा यह निर्भयतापूर्वक कहा कि अतीत के मिथ्यागौरव की बात करना व्यर्थ है। उन्होंने 1893 ई. में अमेरिका के शिकागो नामक नगर में आयोजित "विश्व धर्म सम्मेलन" में हिंदू धर्म पर अपना भाषण देकर सबको चकित कर दिया तथा अपने देश का मान बढ़ाया। उन्होंने अपने देशवासियों की आधुनिक सम्यता के परिप्रेष्य में अपने देश के गौरव को बनाये रखने के लिए निर्देशित किया।

राजाराम मोहन राय, देवेन्द्रनाथ टाकुर, स्वामी दयानन्द, रामकृष्ण परमहंस, महागोविन्द रानाडे, विवेकानन्द जैसे सुधारकों ने अपने लोगों और भाषणों के माध्यम से हिन्दुओं की कुरीतियों, जाति-पाति के भेदभाव और धार्मिक आडंबरों को समाप्त करने की सलाह दी तथा आधुनिक शिक्षा और संस्कृति की ओर उन्मुख होने के लिए दलील दी। पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार ने 19वीं शताब्दी के पुनर्जागरण एवं सुधार आंदोलन का प्रारंभ किया। इसके कारण नयी जागरूकता ने जन्म लिया जिसने समाज एवं हिन्दू धर्म की शुद्धिकरण पर बल दिया तथा सामाजिक-धार्मिक पूर्व धारणाओं, अंधविश्वासों



एवं जातीय अवरोधों को हटाने का लक्ष्य बनाया। इस समय जनता के प्रति में दो स्पष्ट प्रतियाँ थी, जो भारत को अन्धकार पूर्ण समय रूपी पराधीनता से मुक्ति दिलाना चाहती थी।

प्रस्तावित अनुसंधान का महत्व

राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएँ, प्रमुख राजवंश, इनकी प्रशासनिक एवं राजस्व व्यवस्था, सामाजिक-सांस्कृतिक मु. राजस्थान के स्वतंत्रता आन्दोलन, राजनैतिक जन जागरण, एक राजनैतिक एकीकरण की व्याख्या की है। इसके साथ-साथ राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन के ऐतिहासिक विवेचन की विस्तार से रूपरेखा प्रस्तुत की है। राजस्थान के प्रमुख ऐतिहासिक व्यक्तित्व के साथ-साथ उनके कृतित्व का विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है। तत्कालिक रथापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं, स्मारकों, किलों, जो कि राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका के रूप में रहे का विस्तारपूर्वक व्याख्या की गई है। साथ ही तत्कालिक लोक संगीत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, संत सम्प्रदाय एवं लोक देवताओं जिन्होंने राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन में अपनी भूमिका का निर्वहण किया का विस्तार से तुलनात्मक विश्लेषण किया गया है। शोध कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है जो केवल ध्वरात् पर ही खोजबीन करे। इसमें गहन निरीक्षण मुख्य प्रत्यय है। दूसरा मुख्य विचार समस्या का विशिष्टीकरण है। इस प्रकार इस शोध का उद्देश्य है कि शोध एक सुसीमित केरके किसी समस्या का सर्वांगीण विशलेषण है। समस्या का आरम्भ जिज्ञासा से होता है जिज्ञासु व्यक्ति ही शोध कार्य सफलता से कर सकता है।

प्रस्तावित अनुसंधान के उद्देश्य

राजस्थान में क्रांतिकारी आंदोलन के ऐतिहासिक विवेचन में पुस्तक में सैनी जी ने मुख्यतः अलवर रियासत में नवजागरण राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन में अलवर का योगदान, अलवर में आजादी के आंदोलन का शुरूवाती दौर कंसा रहा, अलवर राज्य प्रजामंडल की संघर्ष गाथा, नीमराणा का अलवर में विजय, गोवा मुक्ति आंदोलन अलवर का योगदान के रूप में राजस्थान के क्रांतिकारी आंदोलन का विस्तार से विवेचन किया गया है। साथ ही स्वाधीनता संघर्ष महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक दस्तावेज का विवेचन करना I विश्वयुद्ध के बाद की दीर्घकालीन रणनीति, राष्ट्रीय लहर, आजादी और भारत विभाजन, राष्ट्रीय आंदोलनों की दीर्घकालीन रणनीति, राष्ट्रीय आंदोलन के वैचारिक आयाम, भारत पर औपनिर् शाक प्रभाव आदी का विस्तार से विश्लेषणात्मक विवेचन करना I

प्रस्तावित शोध के निष्कर्ष

18वीं सदी में आन्तरिक संघर्षों से भारत तबाह हो चुका था तथा भारत में आन्तरिक विभ्रम का दौर चल रहा था। यह स्थिति पुरानी व्यवस्था के विघटन और विकास की सामान्य प्रक्रिया में व्यापार, जहाजरानी तथा भारतीय समाज में उत्पादन हितों के आधार पर पूंजीपति वर्ग की सत्ता के उदय के लिए आवश्यक थी। फिर भी इस नाजुक अवधि के दौरान अपने उत्तम तकनीकी और सैनिक एपकरणों तथा सामाजिक आर्थिक सम्बद्धता के साथ यूरोप के और भी अधिक विकसित पूंजीपति 'वर्ग' ने जो धावा बोला उससे विकास अवरुद्ध हो गया जिसके परिणाम स्वरूप पुरानी व्यवस्था के विघटन के समय भारत में उमर रहे नव पूंजीपति वर्ग को भूणावरथा में ही नष्ट कर दिया।

इस तरह जो औद्योगिक क्रान्ति आई उसके परिणाम- स्वरूप इंग्लैंड में एक शक्तिशाली औद्योगिक वर्ग का जन्म हुआ। इस वर्ग ने शनै-शनै. राज्य सत्ता पर अपना अधिकार जमाया और प्राच्य देशों से व्यापार करने के ईस्ट इण्डिया कम्पनी के एकाधिकार को खत्म करने के लिए इस राज्य सत्ता का उपयोग किया। इस वर्ग ने कम्पनी का इसके लिए भी बाध्य किया कि वह ऐसे राजनीतिक और आर्थिक कदम उठाये जो ब्रिटिश उद्योगों के हित में हो।

संदर्भ

1. भगवान दास केला : देशी राज्यों में जन जागृति
2. भारद्वाज शांति : हड़ौती का स्वतंत्रता आन्दोलन(1857-1947) कोटा
3. चौधरी, रामनारायण : बीसवीं सदी का राजस्थान, अजमेर, 1982 ई
4. चौधरी, रामनारायण : बापू मैने क्या देखा, क्या पाया, भारत सरकार, 1964 ई
5. चौधरी, रामनारायण : अंजना देवी चौधरी, अजमेर. 1983 ई.